**सतीश कुमार मित्तल, न्यायाधीश के समक्ष**

**दासा सिंह और अन्य – *अपीलकर्ता/ प्रतिवादी***

***बनाम***

***जसमेर सिंह — उत्तर/ वादी***

***R.S.A.* 2000 का 129**

**13 दिसंबर 2002**

*सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-0.12, आरआई। 6- संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति एक बेटे के पक्ष में सहमति डिक्री - अन्य तीन बेटों द्वारा चुनौती - प्रतिवादियों ने अपने पहले के मुकदमे में स्वीकार किया कि विवादित भूमि संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति है - ट्रायल कोर्ट ने भूमि को संयुक्त हिंदू माना है पारिवारिक संपत्ति को बरकरार रखा जाना चाहिए - सहमति डिक्री - पंजीकृत नहीं - चाहे वैध - धारित, नहीं - प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सहमति डिक्री को अवैध और शून्य ठहराया - क्या विवाहित बेटियां बेटों के बराबर हिस्सेदारी की हकदार हैं संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति - धारित, प्रथम अपीलीय न्यायालय का कोई फैसला नहीं जिसमें बेटियों को संपत्ति में बराबर हिस्सा पाने का हकदार माना गया है, जिसे अलग रखा जा सकता है - केवल पिता और पुत्र ही संपत्ति में बराबर हिस्से के हकदार हैं।*

*माना गया कि ट्रायल कोर्ट ने पहले के मुकदमे में प्रतिवादियों द्वारा की गई स्वीकारोक्ति पर भरोसा किया है, जिसमें सहमति डिक्री थी । यह मानते हुए पारित किया गया कि विचाराधीन भूमि संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति है। पहले के मुकदमे में प्रतिवादियों की यह स्वीकारोक्ति कि विवादित भूमि संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति थी, बहुत स्पष्ट है। अब प्रतिवादियों को अपनी पहले की स्वीकारोक्ति से मुकरने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि विचाराधीन भूमि संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति है। इस प्रकार, मैं संपत्ति की प्रकृति के संबंध में विद्वान प्रथम अपीलीय अदालत के निष्कर्ष को उलट देता हूं और इस संबंध में*

*विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को बरकरार रखता हूं।* (पैरा 15)

इसके अलावा, यह माना गया कि 8 दिसंबर, 1989 की सहमति डिक्री की वैधता के संबंध में, मेरी राय है कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष सही है और इसकी पुष्टि की जानी चाहिए। एक बार जब यह माना जाता है कि विचाराधीन भूमि संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति है तो ऐसी भूमि का हिस्सा सहमति डिक्री द्वारा हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। कथित सहमति डिक्री को निश्चित रूप से पंजीकृत नहीं किया गया था, इसलिए, इसे विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अवैध और शून्य माना गया था।

(पैरा 16)

इसके अलावा, यह माना गया कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह देखते हुए कानून में गलती की है कि दासा सिंह की दो बेटियाँ जो विवाहित थीं, विभाजन में संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में समान हिस्सेदारी की हकदार थीं। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा बताई गई कानून की स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है। यदि संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति का बंटवारा होता है, तो विवाहित बेटियां बेटों के बराबर किसी भी हिस्से की हकदार नहीं होती हैं। बंटवारे की कार्यवाही में केवल मां ही बेटों के बराबर हिस्से की हकदार है। हालाँकि, माँ सहदायिक संपत्ति के बंटवारे के लिए बाध्य नहीं कर सकती। विवाहित बेटियां और बहनें सहदायिकी के बंटवारे पर हिस्सेदारी की हकदार नहीं हैं।

(पैरा 17 एवं 18)

.

बी.आर. वोहरा, एडवोकेट अपीलकर्ताओं के लिए एमएस. जोशी, एडवोकेट, *उत्तरवादी* के लिए.

R.S.A. 2000 की संख्या 130

दासा सिंह और अन्य

बनाम

*अजमेर सिंह* और अन्य

बी.आर.वोहरा, एडवोकेट, अपीलकर्ताओं के लिए, एमएस जोशी, एडवोकेट, उत्तरदाताओं के लिए R.S.A. 2000 की संख्या 174

*अजमेर* सिंह और अन्य

बनाम

दासा सिंह और अन्य

एमएस.जोशी, एडवोकेट, अपीलकर्ताओं के लिए बी.आर. वोहरा, एडवोकेट,उत्तरदाताओं के लिए

R.S.A. 2000 की संख्या 1091

जसमेर सिंह

बनाम

दासा सिंह और अन्य

एमएस. जोशी, एडवोकेट.,अपीलकर्ता के लिए

बी.आर.वोहरा, एडवोकेट, उत्तरदाताओं के लिए

**अदालत का निर्णय**

सतीश कुमार मित्तल, न्यायाधीश.

(१) यह निर्णय निम्नलिखित चार नियमित दूसरी अपील का निपटान करेगा: —

(i) 2000 का आरएसए नंबर 129 **दासा सिंह और ज्ञान सिंह बनाम जसमेर सिंह**

(ii) 2000 का आरएसए नंबर 130 **दासा सिंह और ज्ञान सिंह बनाम अजमेर सिंह और हरदयाल सिंह**

**(iii)** 2000 का आरएसए नंबर 174 **अजमेर सिंह और हरदयाल सिंह *बनाम* दासा सिंह और ज्ञान सिंह**

**(iv)** 2000 का आरएसए नंबर 1091 **जसमेर सिंह *बनाम* दासा सिंह और ज्ञान सिंह**

(२) उपरोक्त अपीलें जसमेर सिंह और उनके दो भाइयों अजमेर सिंह और हरदियाल सिंह द्वारा अपने पिता दासा सिंह और भाई ज्ञान सिंह के खिलाफ दायर किए गए निम्नलिखित दो सिविल मुकदमों से उत्पन्न हुई हैं: -

(i) सिविल सूट नंबर 447-सीएस, दिनांक 8-5-1992 — जसमेर सिंह बनाम दासा सिंह और ज्ञान सिंह

(ii) सिविल सूट नंबर 49, दिनांक 21-12-1992 — अजमेर सिंह और हरदियाल सिंह बनाम दासा सिंह और ज्ञान सिंह

(3) चूंकि दोनों मुकदमों में तथ्यों और कानून के समान प्रश्न शामिल थे, इसलिए, उन्हें ट्रायल कोर्ट द्वारा समेकित किया गया था।

(4) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दासा सिंह के चार बेटे थे, अर्थात् ज्ञान सिंह, जसमेर सिंह, अजमेर सिंह और हरदियाल सिंह। उनकी दो बेटियाँ भी थीं, जिनकी शादी हो चुकी थी और जिनमें से एक की अब मृत्यु हो चुकी है। दासा सिंह का परिवार एक संयुक्त हिंदू परिवार था और राजस्व रिकॉर्ड में 140 कनाल 5 मरला भूमि दासा सिंह के नाम पर दर्ज थी। परिवार में विवाद तब शुरू हुआ, जब दासा सिंह को 8 दिसंबर, 1989 को अपने एक बेटे ज्ञान सिंह के पक्ष में 41 कनाल 11 मरला भूमि के संबंध में एक सहमति डिक्री का सामना करना पड़ा, जिसमें विशिष्ट खसरा नंबर शामिल थे। इस सहमति डिक्री की पीड़ा के कारण शेष तीन भाइयों द्वारा उपरोक्त दो मुकदमे दायर किए गए। एक मुकदमा जसमेर सिंह द्वारा दायर किया गया था और दूसरा अजमेर सिंह और हरदयाल सिंह द्वारा उनके पिता दासा सिंह और भाई ज्ञान सिंह के खिलाफ दायर किया गया था। अपने संबंधित मुकदमों में, उन्होंने दलील दी कि 140 कनाल 5 मरला की विवादित भूमि एक संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति है, जिसमें वे अपने पिता के साथ सहदायिक हैं और उक्त संपत्ति में उनका 1/5 हिस्सा है। आगे दलील दी गई कि वर्ष 1988 में दोनों पक्षों के बीच एक पारिवारिक समझौता हुआ था, जिसमें उपरोक्त भूमि को पांच बराबर हिस्सों में विभाजित किया गया था। लेकिन किसी को कोई विशिष्ट खसरा नंबर नहीं दिया गया, क्योंकि वास्तविक बंटवारा राजस्व न्यायालय के समक्ष बंटवारे की कार्यवाही में किया जाना था। आगे दलील दी गई कि वास्तविक विभाजन किए बिना, उनके पिता दासा सिंह ने 8 दिसंबर, 1989 को अपने एक बेटे ज्ञान सिंह के पक्ष में एक सहमति डिक्री का सामना किया, जिसके तहत 41 कनाल 11 मरला भूमि को हस्तांतरित किया गया था। विशिष्ट खसरा नंबर, बिना किसी कानूनी अधिकार के और उक्त डिक्री पूरी तरह से अवैध और शून्य है।

(5) प्रतिवादी दासा सिंह और ज्ञान सिंह ने संयुक्त रूप से उपरोक्त दोनों मुकदमे लड़े। उनकी दलील थी कि विचाराधीन संपत्ति संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति नहीं है। यह दलील दी गई कि वर्ष 1973 में, पिता और पुत्रों के बीच एक मौखिक पारिवारिक समझौता हुआ था, जिसमें संबंधित पूरी जमीन पिता को दे दी गई थी और प्रत्येक पुत्र को सोने और चांदी के आभूषणों के माध्यम से मुआवजा दिया गया था। इसलिए, दासा सिंह, विचाराधीन भूमि का मालिक होने के नाते, अपने बेटों में से एक के पक्ष में सहमति डिक्री के माध्यम से अपनी भूमि हस्तांतरित करने का हकदार था। मुक़दमे विभिन्न अन्य आधारों पर लड़े गए, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ आवश्यक पक्षों का गैर-जुड़ना भी शामिल था; और परिवार के कर्ता द्वारा किए गए अलगाव को चुनौती देने के लिए वादी का अधिकार क्षेत्र।

(6) विद्वान ट्रायल कोर्ट ने वादी द्वारा दायर मुकदमों पर आंशिक रूप से फैसला सुनाया। यह माना गया कि विचाराधीन भूमि संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति थी, जिसमें प्रत्येक सहदायिक का 1/5 हिस्सा था। हालाँकि, 8 दिसंबर, 1989 की सहमति डिक्री को रद्द करने के संबंध में वादी के दावे को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया था कि संयुक्त हिंदू परिवार में सहदायिक होने के कारण बेटे अपने जीवनकाल के दौरान परिवार के कर्ता द्वारा किए गए अलगाव को चुनौती देने में सक्षम नहीं थे। . ट्रायल कोर्ट के उक्त फैसले के खिलाफ दोनों पक्षों ने अपील दायर की। निर्णय के भाग के विरुद्ध वादी द्वारा दो अपीलें दायर की गईं, जिसके तहत सहमति डिक्री को रद्द करने के संबंध में उनके मुकदमे खारिज कर दिए गए। फैसले के उस हिस्से के खिलाफ प्रतिवादियों द्वारा दो अपीलें दायर की गईं, जिसके तहत यह माना गया कि विचाराधीन भूमि संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति थी, जिसमें प्रत्येक सहदायिक का 1/5 हिस्सा था।

(7) इन सभी चार अपीलों का निपटारा विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा एक सामान्य निर्णय द्वारा किया गया है, जिसके तहत विद्वान ट्रायल कोर्ट के निर्णय को आंशिक रूप से संशोधित किया गया है। 8 दिसंबर 1989 की सहमति डिक्री के संबंध में यह माना गया है कि यह दो आधारों पर अवैध और शून्य है; पहला यह कि यह न्यायालय के साथ धोखाधड़ी थी और दूसरा यह कि यह पंजीकृत नहीं था, इसलिए **भूप सिंह बनाम राम सिंह और अन्य एआईआर 1996 एससी 196** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर यहअवैध और शून्य है, (1) 140 कनाल 5 मरला भूमि के संबंध में

, यह माना गया है कि इस भूमि में से 34 कनाल भूमि दासा सिंह की स्व-अर्जित संपत्ति है और शेष 106 कनाल 5 मरला भूमि संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति है। उक्त संपत्ति में हिस्सेदारी के संबंध में, यह माना गया है कि संयुक्त हिंदू परिवार सात सदस्यों यानी पिता, चार बेटों और दो बेटियों से बना है और उनमें से प्रत्येक 106 कनाल 5 मरला भूमि में 1/7वें हिस्से का हकदार है।

(8) विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के उपरोक्त निर्णय से व्यथित होकर दोनों पक्षों ने इस न्यायालय में उपरोक्त चार नियमित द्वितीय अपीलें दायर की हैं।

(9) वादी जसमेर सिंह, अजमेर सिंह और हरदयाल सिंह के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विद्वान प्रथम अपीलीय अदालत ने संपत्ति की प्रकृति के संबंध में विद्वान ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष को अवैध रूप से उलट दिया है, जिसमें यह माना गया था कि विचाराधीन भूमि पार्टियों की संयुक्त हिंदू परिवार संपत्ति है। विद्वान प्रथम अपीलीय अदालत ने अनुमानों और अनुमानों के आधार पर यह गलत माना है कि 140 कनाल 5 मरला भूमि में से 106 कनाल 5 मरला संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति है और शेष 34 कनाल भूमि दासा सिंह की स्वअर्जित संपत्ति है।

(10) दूसरी ओर, प्रतिवादी दासा सिंह और ज्ञान सिंह के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विचाराधीन पूरी भूमि दासा सिंह की स्वयं अर्जित संपत्ति है, क्योंकि वर्ष 1973 में एक मौखिक पारिवारिक समझौते में, उन्हें पूरी संपत्ति मिल गई थी। अपने पुत्रों को सोने और चाँदी के आभूषण देकर। उन्होंने आगे तर्क दिया कि विद्वान प्रथम अपीलीय अदालत ने 8 दिसंबर, 1989 की सहमति डिक्री की वैधता के संबंध में विद्वान ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष को उलटते हुए गंभीर अवैधता की है।

(11) हालाँकि, दोनों पक्षों के विद्वान वकील यह प्रस्तुत करने में संयुक्त हैं कि विद्वान प्रथम अपीलीय अदालत के फैसले का हिस्सा, जिसके तहत यह माना गया है कि सात सदस्य, दासा सिंह की दो बेटियों सहित परिवार, संयुक्त हिंदू परिवार 106 कनाल 5 मरला की संपत्ति में 1/7वां हिस्सा पाने का हकदार है, गलत और कानून के खिलाफ है। उनके अनुसार, किसी भी परिस्थिति में, विवाहित बेटियों को संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में सहदायिक नहीं कहा जा सकता है।

(12) मैंने पक्षों के विद्वान वकील द्वारा की गई संबंधित दलीलों पर विचार किया है और मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

(13) इन चार अपीलों में निम्नलिखित तीन प्रश्न शामिल हैं:-

(i) क्या विचाराधीन भूमि दासा सिंह और उनके चार बेटों की संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति है और यदि हां, तो संयुक्त हिंदू परिवार के प्रत्येक सदस्य का हिस्सा क्या है?

(ii) क्या दासा सिंह द्वारा अपने पुत्र ज्ञान सिंह के पक्ष में 41 कनाल 11 मरला भूमि के संबंध में 8 दिसंबर, 1989 की सहमति डिक्री को अवैध, शून्य और अमान्य कर दिया गया था?

(iii) क्या विवाहित बेटियाँ संयुक्त हिंदू परिवार की सदस्य हैं और संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में हिस्सेदारी की हकदार हैं?

(14) पहले प्रश्न के संबंध में, मेरी राय है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष सही था और विद्वान प्रथम अपीलीय अदालत ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजी सबूतों को नजरअंदाज करके केवल अनुमानों के आधार पर उक्त निष्कर्ष को आंशिक रूप से उलट दिया। . 140 कनाल 5 मरला भूमि में से, 34 कनाल भूमि को दासा सिंह की स्वयं अर्जित संपत्ति माना गया था, केवल इस धारणा पर कि संपत्ति उनके जीवनकाल के दौरान उनके द्वारा खरीदी या अर्जित की गई थी और शेष भूमि 106 कनाल 5 मरला थी। जो उसे अपने पूर्वजों से विरासत में मिला है। प्री-एम्प्शन डिक्री या सेल डीड द्वारा विभिन्न अवसरों पर 34 कनाल भूमि के अधिग्रहण का जिक्र करते हुए, विद्वान प्रथम अपीलीय अदालत ने निम्नानुसार कहा:

"स्पष्ट रूप से, उपरोक्त कुल 34 कनाल भूमि पार्टियों के पूर्वजों के पास कभी नहीं थी और इस प्रकार यह किसी भी समय पार्टियों की संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति नहीं मानी जा सकती।"

(15) विद्वान प्रथम अपीलीय अदालत ने इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है कि इस संयुक्त हिंदू परिवार के पास एक केंद्रक था और उस केंद्रक की आय से बिक्री या प्री-एम्प्शन डिक्री द्वारा छोटे अधिग्रहण किए गए थे। एक बार जब ऐसा केंद्र स्थापित हो जाता है, तो यह साबित करने की जिम्मेदारी उस केंद्र की मदद से

संपत्ति अर्जित नहीं की गई, उस पार्टी पर आ जाती है, जो इसका दावा करती है। वर्तमान मामले में, प्रतिवादियों ने इस आशय का कोई सबूत नहीं दिया। इसके विपरीत, वादी ने इस आशय के साक्ष्य पेश किए हैं कि ये छोटी संपत्तियां दासा सिंह द्वारा परिवार के कर्ता होने के नाते संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति के केंद्र से अर्जित की गई थीं। एक और पहलू है, जिसे विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने नजरअंदाज कर दिया है। ट्रायल कोर्ट ने पहले के मुकदमे में प्रतिवादियों द्वारा की गई स्वीकारोक्ति पर भरोसा किया है, जिसमें सहमति डिक्री पारित की गई थी, जबकि यह माना गया था कि 140 कनाल 5 मरला की भूमि संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति है। पहले के मुकदमे में प्रतिवादियों की यह स्वीकारोक्ति, कि 140 कनाल 5 मरले की भूमि संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति थी, बहुत स्पष्ट है। पहले के मुकदमे में दायर वादपत्र और लिखित बयान की प्रतियां वर्तमान मामले में साबित की गई हैं, जो प्रतिवादियों द्वारा की गई स्वीकारोक्ति को स्पष्ट रूप से स्थापित करती हैं। अब, उन्हें अपनी पहले की स्वीकारोक्ति से मुकरने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि विचाराधीन भूमि संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति है। इस प्रकार, मैं संपत्ति की प्रकृति के संबंध में विद्वान प्रथम अपीलीय अदालत के निष्कर्ष को उलट देता हूं और इस संबंध में विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को बरकरार रखता हूं और यह माना जाता है कि 140 कनाल 5 मरला की भूमि संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति है।

(16) दूसरे प्रश्न के संबंध में यानी 8 दिसंबर 1989 की सहमति डिक्री की वैधता के संबंध में, मेरी राय है कि विद्वान प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष सही है और इसकी पुष्टि की जानी चाहिए। एक बार जब यह माना जाता है कि विचाराधीन भूमि संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति है, तो ऐसी भूमि का हिस्सा सहमति डिक्री द्वारा हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। कथित सहमति डिक्री को निश्चित रूप से पंजीकृत नहीं किया गया था, इसलिए, **भूप सिंह के मामले (सुप्रा)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर, इसे विद्वान प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा अवैध और शून्य माना गया था।

(17) तीसरे प्रश्न के संबंध में, मेरी राय है कि विद्वान प्रथम अपीलीय अदालत ने यह देखते हुए कानून में गलती की है कि दासा सिंह की दो बेटियां, जो विवाहित थीं, संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में समान हिस्सेदारी की हकदार थीं। विभाजन. यह भी गलत माना गया है कि 106 कनाल 5 मरला भूमि पार्टियों की संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति है, जिसका विभाजन वर्ष 1988 में हुआ था, जिसमें दासा सिंह की विवाहित बेटियां भी हिस्से की हकदार थीं। इस संबंध में, विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:

> 'इसमें कोई शक नहीं कि पिता के जीवनकाल में बेटी को कानूनी रूप से स्थापित स्थिति के अनुसार बंटवारा मांगने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन यह भी समान रूप से तय है कि पैतृक संपत्ति के बंटवारे में बेटियां भी संपत्ति के बराबर हिस्सा पाने की हकदार हैं।" मामले को इस तथ्य के साथ पढ़ें कि रिकॉर्ड पर इस बात के संतोषजनक सबूत नहीं हैं कि बेटियों ने अपने हिस्से छोड़ दिए हैं और इसलिए, 1988 का विभाजन दासा सिंह और उनके चार बेटों को केवल मालिक या 1/5 हिस्सा नहीं बना सकता है। प्रत्येक और उस तारीख को यानी 1988 में दासा सिंह, उनके चार बेटे अजमेर सिंह, जसमेर सिंह, हरदियाल सिंह और ज्ञान सिंह के साथ-साथ उनकी बेटी मोहिंदर कौर और दूसरी बेटी नरिंदर कौर के एल.आर. 1 पाने के हकदार थे। 106 कनाल 5 मरला विवादित भूमि में से प्रत्येक को 7वां हिस्सा देना और मौखिक विभाजन के विपरीत पिता और चार पुत्रों को 1/5वां हिस्सा देना अवैध है।"

(18) विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा बताई गई कानून की यह स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है। यदि संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति का बंटवारा होता है, तो विवाहित बेटियां बेटों के बराबर किसी भी हिस्से की हकदार नहीं होती हैं। बंटवारे की कार्यवाही में केवल मां ही बेटों के बराबर हिस्से की हकदार है। हालाँकि, माँ सहदायिक संपत्ति के बंटवारे के लिए बाध्य नहीं कर सकती। विवाहित बेटियां और बहनें सहदायिकी के बंटवारे पर

हिस्सेदारी की हकदार नहीं हैं। हालाँकि, बँटवारे में अविवाहित बेटियों के भरण-पोषण और उनकी शादी के लिए प्रावधान करना पड़ता है। इस प्रकार, विद्वान प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा दर्ज किए गए उपरोक्त निष्कर्ष में दासा सिंह की बेटी मोहिंदर कौर और उनकी दूसरी बेटी नरिंदर कौर के कानूनी प्रतिनिधियों को हकदार माना गया है। संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में प्रत्येक को 1/7वां हिस्सा प्राप्त करना पूरी तरह से अवैध है और इसे अलग रखा जाता है और यह माना जाता है कि सहदायिक के पुरुष सदस्य यानी पिता और चार पुत्र संयुक्त हिंदू में 1/5वें हिस्से के हकदार हैं।

(19) उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, दासा सिंह और ज्ञान सिंह द्वारा दायर 2000 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 129 और 130 को खारिज कर दिया गया है और अजमेर सिंह द्वारा 2000 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 174 और 1091 को खारिज कर दिया गया है। और हरदियाल सिंह और जसमेर सिंह द्वारा अनुमति दी जाती है। विद्वान प्रथम अपीलीय अदालत के फैसले को आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया है और वादी अजमेर सिंह और हरदयाल सिंह और जसमेर सिंह के मुकदमों पर फैसला सुनाया गया है। 41 कनाल 11 मरला भूमि के संबंध में ज्ञान सिंह बनाम दासा सिंह शीर्षक वाले सिविल सूट नंबर 323 दिनांक 14 सितंबर 1989 में पारित सहमति डिक्री दिनांक 8 दिसंबर 1989 को अवैध, शून्य और शून्य माना जाता है। 140 कनाल 5 मरला की वाद भूमि को पार्टियों की संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति माना जाता है, जिसमें सभी सहदायिक, अर्थात् दासा सिंह, अजमेर सिंह, हरदियाल सिंह, जसमेर सिंह और ज्ञान सिंह संयुक्त कब्जे में हैं और इसके हकदार हैं। प्रत्येक को 1/5वाँ हिस्सा मिलता है।

(20) खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं।

**अस्वीकरण :**

**स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।**

**चिनार बाघला**

**प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी**

**(TraineeJudicialOfficer)**

**अंबाला,हरियाणा**